(b) and (c) Eighth Five Year Plan aims at bringing employment into a sharper focus in a medium term perspective with the goal of reducing unemployment to neglegible level within the next ten years.

The outlay for Rural Development in Eighth Plan has been stepped up considerably to Rs. 30,000 crores and major portion of this is proposed to be allocated to employment programmes. Jawahar Rozgar Yojana (JRY) and Integrated Rural Development Programmes (IRDP) ire the two major poverty alleviation and employment generation programmes. The primary objective of JRY is generation of additional gainful employment for the unemployed and under-employed persons in the rural areas. People below the poverty line constitute the target group. During the Eighth Five Year Plan, it is proposed to create a minimum of 1000 million mandays each year in the form of supplementary employment.

IRDP is a self-employment programme and its oyjective is to enable identified poor families to obtain incremental income for crossing the poverty line. Income generating assets are provided through a mix of subsidy and Bank credit. During the Eighth Five Year Plan, it is proposed to assist about 12.6 million families under IRDP. Preparation of credit plans, substantial increase in per family investment and proper provision of backward and forward linkages will be main thrust areas.

Hiteswar Saikia Committee report on employment

@*255. SHRIMATI VEENA VERMA:

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Hiteswar Saikia Committee on employment recommended limiting of Government's role in employrhent generation; and

(b) if so, what are the precise recommendations of the Committee and what is Government's decision on each of the recommendation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) and (b) The Report of the NDC Committee on Employment, constituted under the Chairmanship of Shri Hiteswar Saikia, Chief Minister, Assam is awaiting consideration of the NDC. Details regarding the recommendations of the Committee can be available after the NDC has considered the Report and taken a view on it$ recommendations.

देश में तकनीकी मिशन की स्थापना

*256. श्रीमती सुषमा स्वराज :
डा0 जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में 17 तकनीकी मिशन स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में इन नवीन मिशनों के द्वारा किन-किन क्षेत्रों को लाभ मिलने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने इनके लाभ ग्राम उपभोक्ता तक पहुंचाने हेतु आवश्यक तंत्र आदि की स्थापना हेतु कोई व्यापक योजना भी तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो ग्राम आदमी को लाभ पहुंचाने हेतु कोई योजना कब तक तैयार की जायेगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य

©Previously starred Question 115, transferred from 3rd May, 1993.

मंत्रालय में राज्य मंत्री और (श्री रंगराजन कुमारमंगलम्) : (क) मिशन मोड में 16 प्रौद्योगिकी परियोजनाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है और उचित स्तरों पर आगामी कार्रवाई करने के लिए योजना आयोग ने इन पर सिद्धांततः स्वीकृति दे दी है। वर्ष 1993–94 के लिए 25 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है।

(ख) देश के समस्त भागों में स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, उद्योगों और अन्य एजेंसियों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा। इन 16 प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के अनेक कार्यकलापों से बेहतर उत्पादों और सेवाओं, रोजगार के बेहतर अवसरों आदि के रूप में समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने की आशा है।

मिशन मोड में ली जाने वाली जो 16 प्रौद्योगिकी परियोजनाएं तय की गई हैं, वे इस प्रकार हैं :–

1. चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियां

2. उन्नत सम्मिश्रों का विकास

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए मॉडल

4. प्राकृतिक आपदाओं को कम करना (भूकम्प और भूस्खलन, चक्रवात और पवन, आपदाएं)।

5. फ्लाई ऐश उपयोगिता

6. नेक्स्ट जेनरेशन मेसिवली पेरेलल सुपर कम्प्यूटर

7. नयी इलैक्ट्रानिकी सामग्री और संघटक

8. माइक्रो इलैक्ट्रानिकी और फोटोनी

9. आर्थिक क्षेत्र में अनुरूपान्तर स्वचालित यंत्र

10. भावी वायु जहाजरानी पद्धति

11. सूचना प्रौद्योगिकियां

12. आई पी एम के अधीन खर पतवार नियंत्रण सामग्री का उत्पादन और अनुप्रयोग

13. प्रौद्योगिकी विकास और जैव उर्वरकों का प्रदर्शन-नीला, हरा, काई और राइजोबियम

14. विभिन्न कृषि मौसम क्षेत्रों में अर्थगहन झींगा मछली जल कृषि

15. अवलम्बनीय विकास के लिए चमड़ा प्रौद्योगिकी मिशन; और

16. क्लीन कोल प्रौद्योगिकियां

(ग) और (घ) जी हां। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके प्रबन्ध तंत्र का गठन किया जा रहा है।

Production of sub standard soap

*257. SHRI T. A. MOHAMMED SAQHY:

SHRI V. GOPALSAMY:

Will the PRIME MINISTER be pleased to stale:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item captioned "Most soaps lack quality" which appeared in the Hindustan Times dated 2nd April, 1993;

(b) if so. the details thereof;

(c) what steps are being taken by Government to improve the quality of the soaps manufactured in India;

(d) whether any penal action has been taken against any of the soap manufacturers for production of sub-standard soap so far: and

(e) if so, the details thereof in each case?